

भारत में शैक्षिक सुधारों पर युवाओं की सोच और उनकी भागीदारी का विश्लेषण

शशि शेखर कुमार आज़ाद¹ and डॉ. मोहित सोनी²

शोधार्थी, विभाग शिक्षा¹

शोध निर्देशक, विभाग शिक्षा²

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सारांश

भारत ने आज अस्तित्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में से एक बनाई है। हालाँकि, पिछले दशकों में असाधारण विकास के बावजूद, आगे और सुधार आवश्यक हैं। भारतीय सरकार ने 21वीं सदी में शिक्षा के वास्तविक महत्व को पहचानते हुए, कानून के माध्यम से ज्ञान आधारित समाज बनाने के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता जताई है। वैश्वीकरण भारत के लिए कई अवसर लेकर आया है, जिसका दक्षिण एशियाई देश अपनी जनसांख्यिकीय और आर्थिक क्षमता के कारण अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकता है। भारत की आधी से अधिक आबादी कामकाजी उम्र की है और पूर्वानुमानों के अनुसार, 2020 तक दुनिया की एक चौथाई श्रम शक्ति भारतीयों की होगी। रोजगार सृजन सरकार के लिए केंद्रीय महत्व का है, क्योंकि इसकी सफलता बाद के चरणों में आर्थिक विकास का इंजन बन सकती है। हालाँकि, सूचना समाज के युग में, केवल एक सुशिक्षित पेशेवर कार्यबल की ही माँग है। इसलिए शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। उपमहाद्वीप के सबसे बड़े देश की शिक्षा प्रणाली चुनौतियों के साथ तालमेल बिठाने का प्रयास करती है। लेकिन सुधार की आवश्यकता के बारे में कोई संदेह नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की सरकारों ने पुरानी व्यवस्था की त्रुटियों को सुधारने, नए विकास को अपनाने और रचनात्मकता और नवाचार को प्राथमिकता देने वाले ज्ञान आधारित समाज का निर्माण करने के लिए सचेत रूप से प्रयास किया है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य युवाओं की मजबूत प्रतिक्रिया के लिए घटना विज्ञान को समझना, एक पहलू पर विशेष ध्यान देना, घटना का प्रक्षेपण, प्रेरणा पर अटकलें और घटना और दृष्टिकोण, विश्वास, समझ और भारत में शैक्षिक सुधार में युवाओं की धारणा को जोड़ना है।

मुख्य शब्द: दृष्टिकोण, धारणा, युवा, शैक्षिक सुधार, भारत।

1. परिचय

समावेशी शिक्षा को विभिन्न तरीकों से परिभाषित किया गया है जो विभिन्न रूप से सक्षम बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को पूरा करती है। पिछले पचास वर्षों में भारत सरकार के प्रयास विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रशासन की पूरी गुंजाइश देने की दिशा में रहे हैं। 1974 में, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) के लिए मध्य-स्तरीय समर्थित योजना शुरू की गई थी, जो आम तौर पर विकलांग बच्चों को स्कूलों में समान अधिकार प्रदान करती है और उनके रखरखाव को प्रोत्साहित करती है। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का पता राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, 1986 से लगाया जा सकता है, जिसने एक लक्ष्य के रूप में सुझाव दिया था, 'सभी स्तरों पर विकलांगों को समान भागीदार के रूप में समग्र समुदाय के साथ शामिल करना, उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और उन्हें साहस और निश्चितता के साथ जीवन का सामना करने के लिए सशक्त बनाना'। 1990 में अपनाए गए सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा ने देश में पहले से निर्धारित विभिन्न चक्रों को और बढ़ावा दिया। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 ने विकलांग छात्रों की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए विशेषज्ञों के सुधार के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006, जो उस प्रणाली को समझाने का प्रयास करती है जिसके तहत राज्य, आम समाज और निजी क्षेत्र को विकलांग लोगों के लिए एक सम्मानजनक जीवन की गारंटी देने और उनके अभिभावकों के लिए समर्थन की दिशा में काम करना चाहिए। नवीनतम प्रगति बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (2009) है जो छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और आवश्यक शिक्षा का विकल्प सुनिश्चित करता है। विकलांग बच्चे की शिक्षा के लिए, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 के अध्याय V से संबंधित प्रदर्शन को पढ़ा जाना चाहिए। पीडब्ल्यूडी अधिनियम की धारा V गारंटी देती है कि विकलांग प्रत्येक बच्चा 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के लिए पात्र है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार। भारत सरकार ने 2010 तक सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समावेशी शिक्षा की नई योजना को गति दी है। विचार यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रयास है कि विविध शिक्षार्थी - विकलांग, विभिन्न बोलियाँ और समाज, विभिन्न घर और पारिवारिक जीवन, विभिन्न रुचियाँ और सीखने के तरीके। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी युवा चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, उनके गुण और कमियाँ मानक शिक्षा के लिए आवश्यक होंगी। स्पष्ट रूप से भारत में शिक्षा नीति ने धीरे-धीरे असामान्य आवश्यकताओं वाले बच्चों और वयस्कों पर ध्यान केंद्रित किया है, और सामान्य स्कूलों में समावेशी शिक्षा एक आवश्यक दृष्टिकोण उद्देश्य बन गई है।

2. साहित्य समीक्षा

बॉयल, क्रिस्टोफर और एंडरसन (2010) समावेश के लिए शिक्षक के दृष्टिकोण के महत्व को समझना स्कूल या संभावित रूप से स्थानीय क्षेत्र में समावेशी शिक्षा की पर्याप्तता को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि जो शिक्षक समावेश के लिए अधिक आश्वस्त हैं, उनके पास ध्यान के प्रति अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण वाले शिक्षकों की तुलना में अधिक नियंत्रित सीखने की स्थिति है। शिक्षकों की भूमिका को कई अध्ययनों में कम करके आंका गया है, जिन्होंने ध्यान और छात्र अनुभवों का अध्ययन किया है। समावेशी कक्षाओं को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है, और यह ध्यान में रखते हुए कि स्कूलों में ध्यान शिक्षकों से शुरू होता है, यह आवश्यक है कि शिक्षकों को उचित संसाधनों तक पहुँच और मजबूत पहल और प्रभावी नीति की व्यवस्था के माध्यम से शिक्षा ढांचे द्वारा समर्थित किया जाए।

मोहम्मद, नोरलिजा (2011) शैक्षिक योजना में गुण नैतिक माप को स्कूली विषयों के माध्यम से सिखाने का एक प्रयास है। पिछले शोध के आलोक में, शिक्षकों के दृष्टिकोण इस पद्धति को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस लेख का उद्देश्य शिक्षकों के दृष्टिकोण पर पिछले शोध को व्यवस्थित रूप से पहचानना है क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रम में मूल्यों को निष्पादित करने में भावनात्मक स्थान उपयोगी है। यह ऑडिट पेपर दो शोध प्रश्न निर्धारित कर रहा था, विशेष रूप से, (1) शिक्षक के दृष्टिकोण के चर और (2) शिक्षकों के दृष्टिकोण की कठिनाइयाँ। अध्ययन समावेशन मॉडल में अवलोकन संबंधी जांच शामिल हैं जो शोध प्रश्नों के साथ पंक्तिबद्ध हैं, अंग्रेजी में वितरित किए गए हैं, और 2009 से 2019 के बीच। इस कुशल जांच ने व्यवस्थित समीक्षा और मेटा-विश्लेषण (PRISMA) तकनीक के लिए पसंदीदा रिपोर्टिंग आइटम लागू किए हैं और प्रासंगिक और दायर किए गए लेख प्राप्त करने के लिए स्कोपस, आयाम और Google विद्वान जैसे वेब क्रॉलर का उपयोग करके 14 संबंधित परीक्षाओं की पहचान की है। मुख्य परीक्षा प्रश्न से, शिक्षकों के गुणों के निष्पादन के दृष्टिकोण के घटकों के रूप में चार विषय उभरे, विशेष रूप से शिक्षकों की शिक्षा, शिक्षकों की सख्त मान्यताएं, शिक्षकों का अनुभव और शिक्षकों के सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण।

ग्रेटिएला डाना बोका (2011) पर्यावरण शिक्षा और जलवायु के लिए शिक्षा आज स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली प्राकृतिक शिक्षा, आने वाले समय में हरित समाज के लिए लोगों के समूह को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और वित्तीय डिजाइन) में अध्ययनरत छात्रों की अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और प्राकृतिक व्यवहार के बीच संबंधों को देखना है। बाया मारे के नॉर्थ सेंटर यूनिवर्सिटी में आयोजित इस अध्ययन में कुल 358 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों की प्राकृतिक शिक्षा, विवेक, छात्रों के दृष्टिकोण और व्यवहार

का आकलन करने के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए लिफ्ट स्केल का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में, यह पाया गया कि शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र पर्यावरण सुरक्षा (स्वयंसेवक, चेतावनी, रुचि, सामग्री का पुनः उपयोग) से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, जिसमें नई वस्तु और "हरित" वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। टी-टेस्ट के प्रदर्शन के कारण, यह आगे बढ़ा कि प्राकृतिक शिक्षा के महत्व के संबंध में उनकी समझदारी की डिग्री में कोई अंतर नहीं था। कनेक्शन परीक्षा के कारण, अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और आचरण कारकों के बीच एक सकारात्मक संबंध पहचाना गया।

ग्रेटिएला, बोका और सरकली (2017) प्राकृतिक शिक्षा और जलवायु के लिए शिक्षा आज स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा दी जाने वाली प्राकृतिक शिक्षा, आने वाले समय में हरित समाज के लिए लोगों के समूह को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों (इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और वित्तीय डिजाइन) से जुड़े कॉलेज के छात्रों की अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और प्राकृतिक व्यवहार के बीच संबंधों का विश्लेषण करना है। बाया मारे के नॉर्थ सेंटर यूनिवर्सिटी में आयोजित इस अध्ययन में कुल 358 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों की प्राकृतिक शिक्षा, विवेक, छात्रों के दृष्टिकोण और व्यवहार को मापने के लिए जानकारी एकत्र करने के लिए लिफ्ट स्केल का उपयोग किया गया। इस अध्ययन में, यह पाया गया कि शैक्षणिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र पर्यावरण सुरक्षा (स्वयंसेवक, चेतावनी, रुचि, सामग्री का पुनः उपयोग) से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं, जो नई वस्तु और "हरित" वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। टी-टेस्ट के प्रदर्शन के कारण, यह आगे बढ़ा कि पारिस्थितिक शिक्षा के महत्व के संबंध में उनकी अंतर्दृष्टि की डिग्री में कोई अंतर नहीं था। कनेक्शन परीक्षा के कारण, विवेक, दृष्टिकोण और आचरण कारकों के बीच एक सकारात्मक संबंध स्थापित किया गया।

रामबर्ग, जोआकिम और लॉफ्टमैन (2013) सफल स्कूल लेखन ने प्रदर्शित किया है कि स्कूल-प्रासंगिक दृष्टिकोण छात्रों के शैक्षणिक और सामाजिक परिणामों के लिए मायने रखते हैं। यहाँ एक अपेक्षित संबंध शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंधों की गुणवत्ता हो सकता है, फिर भी कुछ अध्ययनों ने पता लगाया है कि क्या स्कूल व्यवहार्यता के मुख्य बिंदु वास्तव में शिक्षक जागरूकता के बारे में छात्रों की धारणा से संबंधित हैं, जो इस अध्ययन का प्राथमिक कारण है। स्टॉकहोम में 150 वरिष्ठ-स्तरीय स्कूल इकाइयों से हाल ही में एकत्रित जानकारी के आधार पर, शिक्षक-मूल्यांकित 'स्कूल पहल', 'शिक्षक भागीदारी और सहमति', और 'स्कूल लोकाचार' (n = 2073) के संबंध में स्कूल व्यवहार्यता की जाँच छात्रों द्वारा घोषित स्पष्ट शिक्षक जागरूकता के अनुसार की गई (n = 8022)। दो-स्तरीय सीधे पुनरावृत्ति अध्ययनों ने संकेत दिया कि स्कूल व्यवहार्यता के तीनों भाग छात्रों के बीच देखी गई शिक्षक जागरूकता के उच्च स्तर के पूर्वानुमानित थे। निष्कर्षों से पता

चलता है कि स्कूल पर्याप्तता के ये मुख्य बिंदु शिक्षकों के अपने छात्रों के साथ संबंधों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं।

प्रसोजो, लैटिप और मुकमिनिन (2016) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) समन्वय का 21वीं सदी की शिक्षा में बहुत बड़ा प्रभाव और कई बाधाएँ हैं। इस मिश्रित रणनीति अध्ययन ने इंडोनेशियाई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षण अभ्यासों में आईसीटी के सामंजस्य के साथ-साथ समावेशन बाधाओं के प्रति शिक्षकों के दृष्टिकोण और समझ की जाँच करने की ओर इशारा किया। हमने सूचना वर्गीकरण, अवलोकन और केंद्र एकत्रीकरण वार्तालाप की दो अवधियों के साथ एक-मिश्रण तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया। उत्तरदाता समीक्षा के लिए 234 शिक्षक थे और केंद्र एकत्रीकरण वार्तालाप के लिए 23 सदस्य थे। हमने समीक्षा की सूचना जाँच में माध्य और मानक विचलन का उपयोग किया। फिर, FDG से प्राप्त जानकारी की व्याख्या, व्याख्या, कोडित, विखंडन और व्याख्या की गई। खोजों ने शिक्षा में आईसीटी के समावेश और समावेशन बाधाओं के प्रति इंडोनेशियाई ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों के दृष्टिकोण और धारणा को उजागर किया। इंडोनेशियाई शैक्षिक ढांचे में सुधार के लिए सुझाव और नीति प्रस्ताव पेश किए गए हैं।

3. समावेशी शिक्षा समावेशी शिक्षा का नियम

"विशेष आवश्यकता शिक्षा पर विश्व सम्मेलन: पहुँच और गुणवत्ता" (सलामांका वक्तव्य, स्पेन 1994) में अपनाया गया था और विश्व शिक्षा मंच पर दोहराया गया था। वक्तव्य सरकारों से शिक्षा ढांचे को समावेशी बनाने और समावेशी शिक्षा के नियम को रणनीति के मुद्दे के रूप में अपनाने के लिए कहता है। संयुक्त राष्ट्र के विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसरों के समानीकरण पर मानक नियमों द्वारा विचार की संभावना को भी बरकरार रखा गया है, जो सभी के लिए भागीदारी और संतुलन की घोषणा करता है। समावेशी शिक्षा (IE) को सीखने के माहौल में बाधाओं को कम करके और उसके भीतर सभी शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने की एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है बच्चे के पड़ोस के स्कूल की आयु-उचित कक्षा में जाना, विशेष रूप से अनुकूलित सहायता के साथ (यूनिसेफ 2007)। समावेशी शिक्षा सभी शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए शिक्षा ढांचे की सीमा को मजबूत करने की एक प्रक्रिया है। थाईलैंड में जोमेटिन विश्व सम्मेलन (1990) में, 'सभी के लिए शिक्षा' के उद्देश्य निर्धारित किए गए थे और यह घोषणा की गई थी कि प्रत्येक व्यक्ति (बच्चे, युवा और वयस्क) को शैक्षिक स्वतंत्रता का लाभ उठाने का विकल्प होगा जो उनकी बुनियादी सीखने की जरूरतों को पूरा करेगा। ध्यान एक शैक्षिक पद्धति और सिद्धांत है जो सभी छात्रों को शैक्षणिक और सामाजिक उपलब्धि के लिए अधिक प्रमुख स्वतंत्रता देता है। इसमें सामाजिक, खेल,

अभिव्यक्ति, खेल, संगीत, डे केयर और आफ्टरस्कूल देखभाल, पाठ्येतर, धार्मिक और किसी भी अन्य गतिविधियों के पूर्ण दायरे में भाग लेने की स्वतंत्रता शामिल है।

भारत में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने यूनिसेफ के साथ मिलकर वर्ष 1987 में विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा परियोजना (पीआईईडी) शुरू की, ताकि विकलांग छात्रों को सामान्य स्कूलों में शामिल किया जा सके। हाल ही में, समावेशी शिक्षा की अवधारणा को विकलांग छात्रों के साथ-साथ उन सभी छात्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है जो बोझिल हो सकते हैं। शैक्षिक योजना की इस व्यापक समझ ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ-2005) के निर्माण की तैयारी की है जो एक ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से सभी बच्चों को स्कूल में शामिल करने और बनाए रखने के महत्व को दोहराती है जो हर बच्चे के मूल्यांकन की पुष्टि करता है और सभी बच्चों को गर्व और सीखने के आत्मविश्वास का अनुभव करने के लिए सशक्त बनाता है। 4. समावेशी शिक्षा कार्यक्रम भारत की सार्वजनिक प्राधिकरण अनिवार्य रूप से प्रत्येक बच्चे को आवश्यक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सरकार ने 1947 में देश की आज़ादी के बाद से ही एक विशेष पाठ्यक्रम के इर्द-गिर्द कई दृष्टिकोण अपनाए हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए सबसे समयबद्ध उचित कार्यों में से एक 1974 की विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा (IEDC) योजना थी। कोठारी आयोग (1966) ने स्वायत्तता के बाद के समय में विकलांग बच्चों को पढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। 1980 के दशक में तत्कालीन सेवा कल्याण, भारत सरकार ने विकलांगता बहाली के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों की निगरानी और निर्देशन के लिए एक संगठन की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझा। 1990 के दशक तक, भारत के अनुमानित 40 मिलियन बच्चों में से अधिकांश, जो शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हैं, उन्हें मानक शिक्षा से वंचित रखा जा रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 और कार्य योजना (1992) में असाधारण आवश्यकताओं वाले बच्चों को विभिन्न समूहों के साथ समन्वयित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत सरकार ने 1994-95 में जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना (DPEP) को क्रियान्वित किया। 90 के दशक के उत्तरार्ध में (उदाहरण के लिए 1997 में) समावेशी शिक्षा की सोच को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) में शामिल किया गया। इस कार्यक्रम ने वैश्विक रुझानों के अनुरूप, हल्के से लेकर सीधे विकलांग बच्चों के समन्वय पर असाधारण जोर दिया और 40,000 मिलियन रुपये (लगभग 740 मिलियन अमेरिकी डॉलर) के वित्तपोषण के मामले में उस समय भारत सरकार की सबसे बड़ी अग्रणी परियोजनाओं में से एक बन गई। सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए) को 2001 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया था, जो ऐसी ही एक गतिविधि है। यूईई के तीन महत्वपूर्ण भाग 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की पहुँच, नामांकन और

रखरखाव हैं। एसएसए के तहत एक शून्य बर्खास्तगी रणनीति अपनाई गई है, जो यह सुनिश्चित करती है कि विकलांगता के प्रकार, वर्ग और स्तर से स्वतंत्र प्रत्येक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (सीडब्ल्यूएसएन) को महत्वपूर्ण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। सार्वजनिक पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) 2005 ने समावेशी शिक्षा का एक तरीका निर्धारित किया है। वर्ष 2005 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विकलांग बच्चों और युवाओं की शिक्षा में समावेश के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की। इसके अलावा, वर्ष 2009-10 में IEDC में संशोधन किया गया और इसका नाम "माध्यमिक स्तर पर विकलांगों की समावेशी शिक्षा" (IEDSS) रखा गया, ताकि 9वीं और 10वीं कक्षा में विकलांग बच्चों की समावेशी शिक्षा में सहायता की जा सके। वर्तमान में यह योजना वर्ष 2013 से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) के अंतर्गत आ गई है। इन बच्चों को सामान्य स्कूलों में शामिल करना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें घुलने-मिलने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने में मदद मिल सके।

5. भारत में शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा सुधार

पिछले कुछ वर्षों में, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा (LCE) को वैश्विक मार्गदर्शक संगठनों द्वारा बुनियादी शिक्षा के लिए पसंदीदा मॉडल के रूप में दुनिया भर में तेजी से आगे बढ़ाया गया है, खासकर गैर-औद्योगिक देशों में।

श्रीसफर्थ (2013) उस क्रांतिकारी माहौल पर ध्यान केंद्रित करता है जिसने LCE को न केवल एक यात्रा रणनीति के रूप में शामिल करना शुरू कर दिया है, जिसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों की कार्रवाई के माध्यम से सभी सेटिंग्स में भेजा गया है, बल्कि सभी के लिए शिक्षा जैसे शांतिपूर्ण समझौतों में भी पोषित किया गया है। ये आम तौर पर स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का मतलब है शिक्षार्थी-केंद्रित पद्धतियों की ओर बढ़ना।

हालांकि, कुछ शोधकर्ता LCE की 'रणनीति अधिग्रहण' को 'एक आकार-फिट-सभी', संदर्भहीन 'सर्वोत्तम अभ्यास' के रूप में जांचते हैं, और सवाल करते हैं कि क्या इसे वास्तव में दुनिया भर में एक व्यवस्था निर्णय के रूप में सुझाया जाना चाहिए। ये शोधकर्ता LCE के बेहतर शिक्षण परिणाम लाने के लिए निर्विवाद प्रमाण की स्पष्ट अनुपस्थिति का उल्लेख करते हैं, साथ ही विशेष रूप से गैर-औद्योगिक देशों में इसके उपयोग में निराशा के विभिन्न विवरण भी बताते हैं। वे विभिन्न अनिवार्यताओं को पहचानते हैं जो इन विशिष्ट स्थितियों में LCE को अनुचित बना सकती हैं: सीमित संसाधन, असंगत मूल्यांकन और पाठ्यचर्या ढांचे, अपर्याप्त शिक्षक तैयारी, अनुचित दृष्टिकोण धारणाएं, और सबसे आम तौर पर, सामाजिक मान्यताओं में अंतर जो LCE की

धारणाओं के साथ संघर्ष कर सकते हैं। हालाँकि, इस अंतिम सीमा का अब तक बहुत कम निरीक्षण किया गया है, खासकर भारत में

शिक्षकों की सांस्कृतिक मान्यताओं को संबोधित करने की आवश्यकता

शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के अंदर शिक्षकों की मान्यताओं पर विचार करने के महत्वपूर्ण महत्व को उजागर करने वाले वैश्विक शोधों का एक विकासशील संग्रह है। 1978 की शुरुआत में ही, फेनस्टरमेकर ने अनुमान लगाया था कि शिक्षकों की मान्यताओं की जांच शैक्षिक अन्वेषण के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण निर्माण बन जाएगी। उस बिंदु से इस धारणा को कुछ अन्य लोगों द्वारा दोहराया गया, जिन्होंने शिक्षक शिक्षा और शिक्षण अभ्यासों को बेहतर बनाने के लिए शिक्षकों की मान्यताओं की केंद्रीयता को रेखांकित किया। शोध का प्रस्ताव है कि शिक्षक शिक्षण के बारे में गहराई से स्थापित मान्यताओं के साथ शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों में आते हैं, जो छात्रों के रूप में अध्ययन कक्षाओं में बिताए गए बहुत लंबे समय से आकार लेते हैं, जो उनके द्वारा नई जानकारी को समझने के तरीके के माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। मुनबी (1984) इस ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि यदि शिक्षकों की वर्तमान मान्यताएँ सुधार प्रयास का समर्थन करने वाली धारणाओं के साथ मेल नहीं खाती हैं, तो इसका परिणाम तैयारी द्वारा अपेक्षित परिवर्तन और कक्षा में वास्तव में दिखाए जाने वाले परिवर्तन के बीच एक भ्रम है। ये और विभिन्न शोधकर्ता प्रस्ताव करते हैं कि तैयारी कार्यक्रम, शैक्षिक सुधार या नई पाठ्यचर्या संरचनाएँ जो नई शैक्षणिक तकनीकों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं, वे सम्मोहक हो सकती हैं यदि शिक्षकों ने विकास में छिपे संदेहों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया हो। वे कैंटू के इस निर्णय में सहायता करते प्रतीत होते हैं कि 'नौकरी के विश्वासों को समझने में असमर्थता इन शैक्षिक गतिविधियों को निराशा की ओर ले जाएगी'।

भारत में शिक्षकों की मान्यताएँ

अत्यंत उग्र वैश्विक चेतावनियों के बावजूद, भारत में मौजूदा सामाजिक मान्यताओं की गहन जाँच जो LCE के उपयोग में बाधा डाल सकती है, को अब तक अपनाया नहीं गया है। हालाँकि कुछ लेखकों ने इस संभावना पर प्रकाश डाला है कि भारत में शिक्षण पद्धति कुछ व्यापक सामाजिक दृष्टिकोणों द्वारा बनाई गई है, लेकिन ये गहन और बाहरी शोध के केंद्र बिंदु के बजाय केवल संदर्भ के रूप में अधिक रहे हैं। उदाहरण के लिए, डायर एट अल. (2004) और क्लार्क दोनों ने पाया कि LCE-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम अपना आदर्श प्रभाव डालने में विफल रहे क्योंकि वे शिक्षकों की बुनियादी मान्यताओं और सामाजिक मॉडलों के साथ जुड़ने में

विफल रहे, जिसने उनके शिक्षण को गहराई से प्रभावित किया। इन मॉडलों ने शिक्षकों को किए जा रहे सुधारों से गहराई से जुड़ने से रोक दिया, जिससे उनके प्रशिक्षण में केवल सतही बदलाव आए, जबकि आम शिक्षक केंद्रित विश्वदृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं आया। इसके अतिरिक्त, प्रख्यात शिक्षाविद् कृष्ण कुमार ने एक से अधिक बार सुझाव दिया है कि शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा शिक्षकों के प्रशिक्षण को संशोधित करने में की गई अनदेखी का कारण यह है कि वे उन सामाजिक रूप से स्थापित गुणों को संबोधित करने में असमर्थ हैं, जिन पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आधारित है:

क्लार्क (2001), राव एट अल. (2003), सारंगपानी (2003), गुप्ता (2006) और बत्रा (2009) जैसे कुछ अन्य लोगों ने कहा है कि भारतीय शिक्षकों की पारंपरिक शिक्षण पद्धति लैंगिक अभिविन्यास, स्थिति, सामाजिक असमानता, प्रगतिशील प्रणाली, सूचना प्रसारण आदि पर गहराई से स्थापित सामाजिक दृष्टिकोणों पर आधारित है, जो मौजूदा प्रथाओं को बदलना मुश्किल बनाते हैं। हालाँकि, इस समय तक, शिक्षकों की मान्यताओं के साथ एक ठोस प्रतिबद्धता भारत में शैक्षिक परीक्षा या सुधार प्रयासों में अपना रास्ता नहीं खोज पाई है (झा और झिंगरन, 2005)। झा और झिंगरन की जांच, जो शिक्षकों और अधिकारियों के सामाजिक दृष्टिकोण को भारत में वंचित बच्चों द्वारा वास्तव में सामना किए जाने वाले अलगाव के आधार के रूप में पहचानती है, का तर्क है कि यदि किसी भी तरह से कल्पना की जाए, तो इन पर केवल एक बार की प्रशिक्षण कार्यशालाओं में सीमांत और मध्यम तरीकों से ध्यान दिया गया है, जो गहराई से स्थापित सामाजिक गुणों और प्रथाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। स्कूलों में अलगाव के बारे में देशकाल सोसाइटी की जांच इसी तरह मानती है कि 'हमने अभी एक और अधिक जटिल और गहन स्थापित मुद्दे को उजागर करना शुरू किया है'। जब तक कि भारतीय शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम कौशल के साथ-साथ अधिक गहन सामाजिक मान्यताओं को संबोधित करना शुरू नहीं करते हैं, जिन पर शिक्षकों का प्रशिक्षण आधारित है, वे शिक्षण अभ्यासों को बदलने में प्रभावी नहीं होंगे। भारतीय शिक्षक प्रशिक्षक और नीति निर्माता इन बाधाओं से जूझते रहे हैं, हालांकि शिक्षकों के प्रशिक्षण को आकार देने में शिक्षकों की मान्यताओं की भूमिका पर बहुत कम प्रयोगात्मक परीक्षण प्रमाण हैं, कौन सी विशिष्ट मान्यताएँ LCE की ओर बढ़ने में बाधा बन सकती हैं, और कौन से कारक इन मान्यताओं को बदलने में योगदान दे सकते हैं। यह परीक्षा लेखन में इस छेद को संबोधित करने का प्रयास करती है।

शिक्षा नीति कार्यान्वयन

OECD देशों को 2008 और 2014 के बीच कम से कम 450 शिक्षा सुधार प्राप्त हुए। शिक्षा को शामिल करने वाली तेज़ गति वाली मौद्रिक, सामाजिक और खंड स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा ढांचे को बदलने, सुधारने और भविष्य को आगे बढ़ाने के प्रयास उचित प्रतीत होते हैं। इस बात का बहुत कम सबूत है कि शिक्षा सुधारों का कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं, हालाँकि, इस तथ्य के मद्देनजर कि शैक्षिक प्रभावों का सर्वेक्षण करने की कोशिश की जा रही है और केवल समय-समय पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। किसी भी घटना में, जब सुधार प्रभाव डालते हैं, तो भागीदार परिणामों से प्रभावी रूप से निराश होते हैं और वे आम तौर पर रणनीति निर्माताओं को उनके लिए जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही, वास्तविक चक्रों के बारे में बहुत कम जानकारी है जो आदर्श परिणाम देते हैं, या देने चाहिए। इन चक्रों को "रणनीति की नींव और गतिविधि के क्षेत्र में इसकी संपत्ति के बीच" अक्सर रणनीति उपयोग के रूप में संदर्भित किया जाता है, भले ही परिभाषा पर कोई सहमति न हो।

कार्यान्वयन की मुख्य चुनौतियाँ

जैसे-जैसे हमारी अर्थव्यवस्थाएँ और सामाजिक व्यवस्थाएँ आधुनिक से सूचना आधारित होती जा रही हैं, शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण होती जा रही है। शिक्षा ढाँचे अब पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हैं, ताकि उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और योग्यताएँ दी जा सकें, समृद्धि और गुणों की नई माँगों के बावजूद, युवा पीढ़ी को हमारी तेज़ रफ़्तार, वैश्विक अर्थव्यवस्था की योजना बनाने और उसमें योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जा सके। हालाँकि, शिक्षा रणनीतियाँ कक्षा में नहीं पहुँच पाती हैं, और कमज़ोर निष्पादन उपायों के कारण अपने नियोजित परिणाम प्राप्त करने में विफल हो जाती हैं। लेख में उपयोग को व्यवहार्य होने से रोकने वाले कई कारणों का खुलासा किया गया है। अन्य बातों के अलावा, हम फ्रेमवर्क स्तर पर दृष्टिकोणों को परिभाषित करते समय उपयोग उपायों पर ध्यान न देने, इस बात की स्वीकृति की कमी कि इन परिवर्तन उपायों के लिए केंद्र में व्यक्तियों को शामिल करने की आवश्यकता है और नए जटिल प्रशासन ढाँचों के अनुकूल होने के लिए निष्पादन संरचनाओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता को उजागर कर सकते हैं। इन कदमों के लिए सर्वेक्षण की आवश्यकता है वर्तमान उपयोग के तरीके यह जाँचते हैं कि क्या वे 21वीं सदी में शिक्षा नीति निर्माण के लिए समायोजित हैं और विशेष रूप से, चाहे वे विशेषज्ञ चक्रों के विकास को बनाए रख सकें जो दृष्टिकोण बातचीत में उपलब्धि में योगदान दे सकते हैं। कार्यान्वयन पर अपर्याप्त ध्यान शिक्षा को

चालक के रूप में समीक्षा करें 21वीं सदी की शुरुआत से दृष्टिकोण में बदलाव को संबोधित करता है। इस कदम ने रणनीति निर्माताओं और विभिन्न भागीदारों को स्कूलों की प्रस्तुति पर अधिक ध्यान केंद्रित करने और स्कूलों में दी जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता और सीमा के बारे में अपनी धारणाओं को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। सरकारों ने इन धारणाओं पर प्रतिक्रिया करने के लिए सुधारों को अपनाया है। किसी दिए गए ढांचे के लिए सुधारों की मात्रा बहुत बड़ी हो सकती है: उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया में, 2008 और 2014 के बीच 38 सार्वजनिक सुधार पेश किए गए जबकि आयरलैंड ने इसी अवधि में 23 सुधार किए। उदाहरण के लिए, एक देश में शिक्षकों को शैक्षिक परिणामों के मूल्य और प्रकृति को बेहतर बनाने, शिक्षकों को तैयार करने के तरीके में सुधार करने और छात्रों का मूल्यांकन करने के तरीके को बदलने की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, यह स्पष्ट नहीं है कि परिभाषित रणनीतियाँ "गतिविधि के क्षेत्र में" परिणाम उत्पन्न करती हैं या नहीं। शायद ही कोई अध्ययन वास्तव में सुधार प्रभाव को रिकॉर्ड करता है या यह निर्धारित कर सकता है कि कौन से तत्व दृष्टिकोण की समृद्धि में योगदान करते हैं। शिक्षा में रणनीति के परिणामों को मापना भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वे दिखने में समय लेते हैं, और इस तथ्य के मद्देनजर कि सीखने के निष्पादन परिणामों को एक विशिष्ट दृष्टिकोण के लिए श्रेय देना बहुत मुश्किल हो सकता है।

परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में कार्यान्वयन

कार्यान्वयन के विचार में यह संभावना अंतर्निहित है कि जो व्यवस्था लागू होती है, वह शिक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए, स्कूल स्तर पर एक नया शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना आम तौर पर स्कूलों और शिक्षकों की प्रथाओं, उनकी मान्यताओं और उपयोग की जाने वाली सामग्रियों को बदलने का सुझाव देता है। दूसरी ओर, नए स्कूल अनुदान व्यंजनों को प्रस्तुत करने वाली व्यवस्था के लिए क्षेत्र के अग्रदूतों और प्रशासकों को व्यक्तिगत स्कूलों और स्थानीय शिक्षा ढांचे की देखरेख और वित्तपोषण के तरीके को बदलने की आवश्यकता होती है। हालाँकि, शिक्षा में सुधार करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि अमेरिकी राज्य वित्त पोषित स्कूलों के बारे में हेस में संकेत दिया गया है, "स्कूल और क्षेत्र व्यवसाय नहीं छोड़ते" और शिक्षा और सीखने में अपने सामान्य अभ्यासों का पालन करते हैं। जैसा कि खुले क्षेत्र की गतिविधियों पर एक जांच से संकेत मिलता है, शिक्षा के लिए व्यवसाय के रूप में हमेशा की तरह बने रहने और विभिन्न देशों में बदलाव का विरोध करने की एक गहरी परंपरा है। सुधारों की लागत और परिणामों के बारे में भेद्यता को देखते हुए, भागीदार विकसित होने के बजाय व्यवसाय के रूप में हमेशा की तरह बने रहने की ओर झुक सकते हैं

जटिल शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तन लाना

लेखन में चल रही प्रगति ने प्रदर्शित किया है कि किस तरह शिक्षा उत्तरोत्तर जटिल परिस्थितियों में फलित हो रही है, जो वर्तमान शिक्षा ढाँचों को प्रशासित करने के तरीके को प्रभावित करती है।

जटिल ढाँचों को नए निर्माणों और नई प्रथाओं द्वारा वर्णित किया जाता है जो विभिन्न मनोरंजनकर्ताओं के बीच संचार के कारण उत्पन्न होते हैं। शिक्षा रणनीति से जुड़ने वाले मनोरंजनकर्ताओं की संख्या और प्रकार विकसित हुए हैं। प्रांतीय और पड़ोस के निदेशक, स्कूल प्रतिनिधि, प्रशासक, शिक्षक, अभिभावक और विभिन्न मनोरंजनकर्ता गहरी जड़ें जमाए हुए और काफी हद तक निजी विश्वास ढाँचों के आधार पर शिक्षा के अपने दृष्टिकोण को ढालने में तत्पर हैं। ये मनोरंजनकर्ता शिक्षा के लिए क्या प्रदान करने की आवश्यकता है, इस बारे में गर्म राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेते हैं और स्कूलों में नई रणनीतियाँ लाने के लिए गतिविधियाँ करते हैं। इन विकासों ने गतिशीलता और निष्पादन के विभिन्न स्तरों के बीच संबंधों को बदल दिया है। कुछ ढाँचों में, विकेंद्रीकरण स्थानीय और क्षेत्रीय प्रमुखों और क्षेत्र और स्कूल अग्रदूतों को नीति निर्माण चक्र में अधिक आकलन करने और कुछ पड़ोस की ज़रूरतों के लिए रणनीतियों को समायोजित करने की अनुमति देता है। कुल मिलाकर, शिक्षा ढाँचे मूल रूप से ऊपर से नीचे के डिजाइन से हटकर अधिक समतल कनेक्शन की ओर जा रहे हैं जिसमें व्यवस्था और सह-विकास सब एक साथ हैं। ये ढाँचे गैर-सीधे हैं; वे अपने स्वयं के विकास को आकार देने के लिए इनपुट पर निर्भर करते हैं। वे विभिन्न समय-पैमाने पर और एक ही समय में कुछ स्तरों पर काम करते हैं

ये नए तत्व रणनीति के उपयोग के लिए अतिरिक्त कठिन परिस्थितियाँ बनाते हैं। खुले संगठनों में परिवर्तन कार्यक्रम आम तौर पर दृष्टि की कमी, संप्रेषित करने में कमी या नगण्य परिवर्तनों और प्राथमिक परिवर्तनों के बीच किसी प्रकार का सामंजस्य स्थापित करने में असमर्थता जैसे कारणों से विफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, विश्वास बनाने और बनाए रखने का मुद्दा जटिल ढाँचों में महत्वपूर्ण है। नए घटकों को विभिन्न कलाकारों को उनकी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार मानना संभव बनाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकारें वास्तव में रणनीति बातचीत के सभी हिस्सों को नियंत्रित नहीं करती हैं। साथ ही, ठोस जिम्मेदारी को शिक्षा ढाँचों की क्षमता को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए विकास: OECD राष्ट्रों ने कक्षा, विद्यालय, पड़ोस और सार्वजनिक स्तरों पर विकास और उन्नति के लिए जिम्मेदारी का उपयोग करने के तरीकों की खोज की है।

6. निष्कर्ष

परिणाम युवा राजनीतिक सहयोग अधिकारों की विकासशील बातचीत में नए आयाम जोड़ते हैं और विशेष रूप से स्कूलों में। इस तथ्य के बावजूद कि अध्ययन कक्ष स्तर पर लोकप्रियता आधारित छात्र प्रतिबद्धता से संबंधित लेखन का एक विकासशील वर्गीकरण है, छात्र हित की बड़ी सेटिंग्स से संबंधित लेखन में एक कमी है, विशेष रूप से स्कूल-व्यापी, शैक्षिक समिति या सामान्य स्तर पर, जिसे इस अध्ययन ने बदलने का प्रयास किया है। डेटा गतिशील में युवाओं के समावेश के खिलाफ पारंपरिक विवादों के एक हिस्से को जटिल बनाता है, विशेष रूप से युवाओं की देखभाल की कमी और अयोग्यता के आरोप। यह बचपन की स्थिति के रूप में युवाओं की सामाजिक रूप से पर्याप्त उत्पत्ति को और अधिक जटिल बनाता है, इस प्रकार युवाओं को एक सामाजिक, राजनीतिक, वैध और नैतिक स्थिति के रूप में फिर से परिभाषित करने की मांग करता है। यह देखते हुए कि किस तरह युवाओं ने राजनीतिक विमर्श और गतिविधि में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, युवाओं का अर्थ उनकी दुनिया को और अधिक सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना चाहिए।

7. संदर्भ

1. बॉयल, क्रिस्टोफर और एंडरसन, जोआना और एलन, केली-एन. (2014)। समावेशी शिक्षा के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण का महत्व। 10.1163/9789004431171_008।
2. मोहम्मद, नोरलिजा। (2017)। पाठ्यक्रम में मूल्यों के प्रति शिक्षकों का दृष्टिकोण: एक व्यवस्थित साहित्य समीक्षा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन। 24. 1075-1087।
10.37200/IJPR/V24I5/PR201782।
3. ग्रेटिएला डाना बोका। (2012)। पर्यावरण शिक्षा और छात्रों की धारणा, स्थिरता के लिए।
स्थिरता 2019, 11, 1553; doi:10.3390/su11061553
4. ग्रेटिएला, बोका और साराक्ली, सिनान. (2018). पर्यावरण शिक्षा और छात्रों की धारणा, स्थिरता के लिए।
स्थिरता. 11. 1553. 10.3390/su11061553.
5. रामबर्ग, जोआकिम और लॉफ्टमैन, सारा और अल्मक्रिस्ट, यल्वा और मोडिन, बिट्टे. (2018). स्कूल की प्रभावशीलता और शिक्षक देखभाल के बारे में छात्रों की धारणा: एक बहुस्तरीय अध्ययन. स्कूलों में सुधार. 22.
55-71.10.1177/1365480218764693.

6. प्रसोजो, लैटिप और मुकमिनिन, अमीरुल और हबीबी, अखमद और हेंड्रा, रॉबी. (2013). स्कूलों में आईसीटी को एकीकृत करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का निर्माण: शिक्षकों का दृष्टिकोण, धारणा और बाधाएँ। गुणवत्ता - सफलता तक पहुँच। 20. 45-50।
7. रोमेन विएनेट। (2017)। शिक्षा नीति कार्यान्वयन: एक साहित्य समीक्षा और प्रस्तावित रूपरेखा। 8 दिसंबर 2017 के उसी दस्तावेज़ को रद्द करता है और प्रतिस्थापित करता है।
8. कामिला लुडविकोव्स्का। (2017)। भारत में शैक्षणिक शिक्षकों की बहुसांस्कृतिक क्षमता पर छात्रों की धारणा का गुणात्मक अध्ययन। खंड 8, संख्या 2, 2017, पृष्ठ 29-42
9. असमाली, मेहमत। (2017)। युवा शिक्षार्थियों का दृष्टिकोण और अंग्रेजी सीखने की प्रेरणा। नोविटास-रॉयल (युवा और भाषा पर शोध)। 11. 53-68.
10. ड्रेलिंगा, एल्गा और ज़रीना, सैड्रा और इलिस्को, डिज़िट्रा और सिलोवा, लारिसा। (2017)। सामाजिक धारणाएँ लातविया में एक अच्छा शिक्षक होने के बारे में। समाज। एकीकरण। शिक्षा। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन की कार्यवाही। 1. 130. 10.17770/sie2017vol1.2392।